ले रहे हैं। दोनों के नियम एक होने चाहिएं, दो रुपए या ढाई रुपए पर चैनल लिया जाए। वही सही है, लेकिन उन्हें यह भी आदेश दिए जाएं कि फ्री टू एअर चैनल्स को, बगैर चैनल्स के जो ऑपरेटर्स हैं, जो आपके चैनल्स को दिखला रहे हैं, चाहे टाटा स्काइ दिखला रहा है या जी दिखला रहा है, जो फ्री टू एअर चैनल्स है, उन्हें फ्री दिखलाएं। यह मेरा आपसे निवेदन है और उधर ऑपरेटर्स से पैसा न लिया जाए, जो कि यह कंटेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति जी, बेसिक टिअर की फी लेकर इसको हम कैसे लगाएंगे? फ्री टू एअर का मतलब यह नहीं है कि पूरा फ्री घुस गया है। ऐसा नहीं है। उनको तो एक माध्यम के द्वारा भेजना है, एक माध्यम की तरह उसको पेश करना है और उस माध्यम के लिए बेसिक टिअर भी होता है।

श्री सभापति: क्या बोल गए आप?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सर, मैंने कहा कि फ्री टू एअर का मतलब यह नहीं है कि पूरा मुफ्त में आपके घर में घुस जाए। उसको घुसाने के लिए भी कोई इंतजाम करना चाहिए और उस इंतजाम के लिए बेसिक टिअर फी तो लेना ही चाहिए। यह जो अभी सर्विस टैक्स है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री महेन्द्र मोहन: जरुर लें। दो, ढाई रुपए जरुर लें, लेकिन लाखों रुपए उधर से ले रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: आप सुनिए तो ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। हमारे पास ऐसी कोई निश्चित शिकायत किसी ग्राहक ने अभी तक नहीं की है कि मुझे ठगकर, जो रेट है उससे, ज्यादा पैसा मेरे से वसूल किया गया है। अगर एक भी शिकायत आएगी, तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द करने का हमारे पास प्रावधान है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Camps for Sri Lankan refugees

*583. DR. K. MALAISAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the refugees who fled to Indian refugee camps from Sri Lanka during the recent encounter between LTTE and the Sri Lankan

Army in Sri Lanka, are being taken care of well by Indian Government through the State;

(b) whether there have been any instances recently of protest, demonstrations and road roko by the Sri Lankan refugees in Ramanathapuram District in Tamil Nadu against the State Government, alleging ill-treatment, corruption, sex insults, etc.; and

(c) if so, the remedial measures taken and whether they are adequate and effective?

THE MINISTER OF STAE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MANIKRAO GAVIT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) On 07.07.2006 due to some dispute between the refugees and an N.G.O. and the alleged assault of a young boy apprehended for theft by the NGO and handed over to the police, the refugees in the Mandapam camp went on a road roko agitation. The matter was amicably settled followig intervention of revenue and police officials.

State Rural Road Development Agency

*584. SHRIMATI SUPRIYA SULE:

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering to make the State Rural Road Development Agencies responsible for proper utilization of funds sanctioned for rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and closely monitor the progress of work and have regular review meetings with the implementing agencies;

(b) whether till October, 2006 as many as 57,444 road projects, worth Rs. 34,584.52 crores were sanctioned and Rs. 19,915.69 crores were released; and

(c) if so, what is the total number of roads covered under this programme?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) According to the Programme Guidelines of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), each State is required to identify a State level autonomous agency called the State Rural Road